स्वरोजगार से दूर होगी बेरोजगारी

—गौरव कुमार

देश के ग्रामीण अंचलों में युवा बेरोजगारी की दर काफी अधिक है। हमारा प्रयास इन युवाओं की बेरोजगारी और असंतोष दूर करने के प्रति होना चाहिए। इस हेतु कई अहम् कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ एक अन्य अहम् सवाल यह भी है कि क्या सभी बेरोजगार युवाओं को सरकार रोजगार दे सकती है? इतनी बड़ी आबादी को रोजगार देना एक दुरुह कार्य है। किंतु उनमें स्वरोजगार और उद्यमशीलता की भावना भरकर अवश्य बेरोजगारी दूर की जा सकती है।

आज भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश बन चुका है। यह स्वाभाविक है कि जिस देश में सबसे ज्यादा युवा होंगे वह देश सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज होगा और प्रगतिशीलता के नए शिखर तक पहुंचेगा। किन्तु यह तभी संभव है जब इन युवाओं को सही दिशा मिले। आज देश के हर हिस्से से युवा बेरोजगारी, युवा असंतोष की खबरें प्रायः सुनने में आती हैं। आज देश कुशल या दक्ष लोगों की समस्या से भी जूझ रहा है। वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत की कार्यशील आबादी का अनुपात काफी अधिक है, किन्तु इसमें दक्षता का अभाव है। ऐसे में आज देश में श्रम की जरुरत से अधिक कुशल श्रम की है। और इस दिशा में कौशल विकास जैसी योजनाएं और कार्यक्रम राष्ट्रीय आर्थिक विकास के वाहक बन सकेंगे। इससे ग्रामीण युवा सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे।

केंद्र सरकार ने देश में युवाओं को रोजगार दिलाने और उनमे कौशल विकास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अहम् कदम उठाए है। केंद्र सरकार कौशल विकास और उद्यमशीलता के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति भी जारी कर चुकी है। साथ ही देशव्यापी राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की भी औपचारिक रूप से शुरुआत की गई है। बात जब बेरोजगारी की हो, वहां आज कौशल विकास एक अहम् कड़ी के रूप में स्थापित हो चुका है। रोजगार और कौशल का रिश्ता और महत्व काफी अधिक है और सरकार इस दिशा में बखूबी काम कर रही है। कौशल विकास आज के आधुनिक और तकनीकी विश्व में बेहद महत्वपूर्ण है और इसके प्रति हमारी चिंता इस वजह से भी बढ़ी है क्योंकि बढ़ती आबादी और रोजगार के बीच व्यापक अंतर आ चुका है। इसे पूरा करने में कौशल विकास जैसे माध्यम उपयोगी और कारगर हैं।

रोजगार और कौशल की दशा

आज वैश्विक स्तर पर रोजगार एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। लगातार बढ़ती आबादी के लिए रोजगार सृजन सभी सरकारों के लिए एक चुनौती है। इससे पार पाना वर्तमान में काफी कठिन भी लग रहा है। भारत की स्थिति इस सन्दर्भ में और भी गंभीर बनी हुई है। इस दिशा में सरकार का प्रयास न केवल रोजगार सृजन बल्कि कौशल विकास की तरफ होना भी एक सुखद संकेत है। **आज ग्रामीण युवाओं के रोजगार और उनके कौशल के प्रति सबसे अधिक चिंता व्यक्त की जाती है। इस दिशा में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के रूप में केंद्र सरकार ने अभिनव पहल की है। यह अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है।** इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर ऐसे कार्यों में दक्ष बनाया जाएगा जिसकी मांग विदेशों तक हो। इससे उन्हें दुनिया में कहीं भी रोजगार पाने में कठिनाई

नहीं होगी। इस योजना का एक अन्य मकसद 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के पूरक के रूप में योगदान देना भी है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे रोजगार और कौशल विकास के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं किन्तु इस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता वर्तमान में इसलिए भी महसूस की जा रही है क्योंकि वर्तमान की वैश्विक अर्थव्यवस्था विशेषज्ञता व दक्षता आधारित होती जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक सम्पूर्ण विश्व में करीब 5.5 करोड़ दक्ष लोगों की कमी है। इनमें नर्स, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर आदि जैसे कार्य शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो भारत में 4.7 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास इन कार्यों की दक्षता तो है किन्तु उनके पास सम्बंधित रोजगार नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी खराब है। कई तकनीकी दक्षता प्राप्त और कुशल लोग रोजगार के कारण किसी अन्य कार्यों में संलग्न हैं। इस तरह की स्थितियों के बीच दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास जैसी योजना आरम्भ करना एक महत्वपूर्ण कदम है।

आज देश कुशल या दक्ष लोगों की समस्या से जूझ रहा है। वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत की कार्यशील आबादी का अनुपात काफी अधिक है, किन्तु इसमें दक्षता का अभाव है। राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण के 68 वें चक्र 2012 के अनुसार भारत में कुल श्रमबल करीब 472.9 मिलियन है। 15 से 59 आयु वर्ग की कार्यबल आबादी का हिस्सा सम्पूर्ण जनसंख्या का करीब 60 प्रतिशत है इस श्रम बल का बेहतर तरीके से लाभ नहीं लिया जा पा रहा है वह भी केवल इस वजह से की वे दक्ष नहीं हैं। **आज देश की कुल कार्यशील आबादी का करीब 53 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र में लगा है जहां यह मान लिया गया है कि दक्षता की आवश्यकता नहीं होती। जबकि वास्तविकता यह है कि आज आधुनिक कृषि में सबसे अधिक दक्षता की आवश्यकता है।** दक्षता की कमी भी कृषि के पिछड़ेपन की एक वजह हैं। इसी प्रकार करीब 93 प्रतिशत लोग अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं जहां पर भी दक्षता की जरुरत लगभग महसूस नहीं होती। किन्तु इन क्षेत्रों के श्रमिक यदि दक्षता प्राप्त कर ले तो उनकी स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हो सकता है। इस तरह से इन क्षेत्रों के श्रमिकों के प्रति जारी चिंता को भी समाप्त किया जा सकेगा।

देखा जाए तो दक्षता विकास कार्यक्रमों को भी शक्ल देने की आवश्यकता है, इस तरह की योजनाओं को शुरू करने के लिए सरकार के वर्तमान प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। आज देश में बहुसंख्यक आबादी को बेहतर जीवन–स्तर देने की चुनौती खड़ी है। यदि रोजगार की मांग और आपूर्ति के बीच खाई को कम किया जाए तो आय के स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है। यह गरीबी कम करने में मददगार हो सकती है, देश की आर्थिक सेहत में सुधार लाया जा सकता है। सबसे बढ़कर देश के ग्रामीण अंचलों में विकास की नई दिशा बनाई जा सकती है जो ग्रामीण विकास का नया स्वरुप होगा। वैसे देश में आजादी के बाद से ही कई ऐसी नीतियां लाई गई जो हमारे देश के ग्रामीण अंचलों के विकास से प्रत्यक्षतः जुड़े हुए थे। ऐसी सैकड़ों नीतियां और योजनाएं क्रियान्वित की गई जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की दिशा अग्रोन्मुख हो।

ग्रामीण रोजगार और कौशल विकास के पूर्ववर्ती प्रयास

गरीबी को प्रभावी तरीके से दूर करने और ग्रामीण विकास की दिशा तीव्र करने के लिए केंद्र सरकार ने मनरेगा जैसे महात्वाकांक्षी कार्यक्रम को शुरू किया। आंकड़े बताते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के आर्थिक–सामाजिक विकास की नई इबारत लिखी जा चुकी है। इससे बेरोजगारी जैसी समस्या का भी प्रभावी निदान हुआ है, साथ ही इससे लोगों का सशक्तीकरण और ग्रामीण मजदूरी की दर में भी काफी इजाफा हुआ है। एक अन्य योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो 25 दिसंबर, 2000 को शत–प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी, इसने भी इस दिशा में काफी बेहतर काम किया है। एक अध्ययन में यह बात रेखांकित की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब सड़क निर्माण पर 10 लाख का निवेश होता है तो करीब 163 लोग गरीबी के चक्र से बाहर निकलते हैं। इसी तरह एक अन्य रोजगार संबंधी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसे 1 अप्रैल, 1999 से शुरू किया गया, ग्रामीण रोजगार से जुड़ी योजना थी। नवीन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कुछ प्रमुख मिशन और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। स्वयंसहायता समूह भी इसी तरह की अन्य योजना है जो समान समस्या से जूझ रहे लोगों का एक छोटा समूह है। समूह के सदस्य एक–दूसरे की समस्या के निदान के लिए सहयोग करते हैं। इसका समन्वित प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में रोजगार के प्रति एक आशा के रूप में दिखता है और वे अपने समाज के साथ जुड़े रहना ज्यादा पसंद करते हैं। कौशल विकास कर रोजगार दिलाने वाली जम्मू–कश्मीर की योजना 'हिमायत' की तर्ज पर देश के सर्वाधिक नक्सल–प्रभावित क्षेत्रों के लिए 'रोशनी' नामक परियोजना शुरू की गई है। 7 जून, 2013 को इस नए कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। इस योजना को नक्सल–प्रभावित 9 राज्यों के 24 जिलों में पहले चरण में शुरू हुआ जा रहा है। अगले तीन वर्षों में इस योजना पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना के तहत करीब 50 हजार युवाओं जिसमें आधी महिलाएं होंगी, को विभिन्न प्रकार के कौशलपरक प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार दिलाया जाएगा जो खुदरा, स्वास्थ्य, टेक्सटाइल, निर्माण, वित्तीय व बीमा क्षेत्रों से सम्बंधित रोजगार होंगे।

इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और कौशल विकास के लिए वैसे कई प्रयास किए गए हैं, किन्तु इनका अपेक्षित परिणाम नहीं आ सका और ये किसी न किसी रूप में समस्याओं का समाधान नहीं कर सके।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

देश में करीब 60 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। रोजगार के लिए उपयुक्त कौशल प्राप्त करके ये युवा परिवर्तन के प्रतिनिधि हो सकते हैं। वे न केवल अपने जीवन को प्रभावित करने के काबिल होंगे बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है। इस दिशा में कदम उठाते हुए कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय का गठन किया गया है, जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में जुटा है। इसके तहत सालभर में 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाया जाना है। कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) और उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित होगा। इससे रोजगार–परक कौशल प्रदान करने की बाध्यता बढ़ जाएगी। कार्यक्रम के तहत तृतीय पक्ष आकलन संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन और प्रमाणपत्र के आधार पर प्रशिक्षुओं को नकद पारितोषिक भी दिया जाना है। नकद पारितोषिक औसतन 8,000 रुपये प्रति प्रशिक्षु होगा। इस तरह के कौशल प्रशिक्षण एनएसडीसी द्वारा हाल ही में संचालित कौशल अंतर अध्ययनों के जरिए मांग के आकलन के आधार पर दिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मुख्य रूप से श्रम बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे लोगों पर जोर होगा और विशेषकर कक्षा 10 व 12 के दौरान स्कूल छोड़ गए छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस योजना के तहत अनुमानतः कुल 1120 करोड़ रुपये के परिव्यय से 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसमें पूर्व शिक्षा–प्रशिक्षण को चिह्नित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस मद में 220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। युवाओं को जुटाने तथा जागरुकता के लिए अलग से 67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। युवाओं को कौशल मेलों के जरिए जुटाया जाएगा और इसके लिए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय आधारित संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। कौशल व उद्यम विकास वर्तमान सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

नवगठित कौशल व उद्यम विकास मंत्रालय की "मेक इन इंडिया" अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अभियान भारत को एक विनिर्माण केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए अहम पहल है। विकासशील अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र समेत सभी क्षेत्रों की मांग के अनुसार प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करने में इस मंत्रालय की अहम भूमिका है। वर्ष 2022 तक 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में प्रयास मिशन के तौर पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत तीन संस्थान कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कौशल विकास प्रयासों को नीतिगत दिशा दे रही है और इनकी समीक्षा भी कर रही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय प्रधानमंत्री की परिषद के नियमों को लागू करने के लिए रणनीतियों पर कार्य कर रहा है। एनएसडीसी एक गैर–लाभ कंपनी है और गैर–संगठित क्षेत्र समेत श्रम बाजार के लिए कौशल प्रशिक्षण की जरुरतों को पूरा कर रही है।

भारत ने विश्व में सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना ली है। उम्मीद है कि भारत शीघ्र ही विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। उम्मीद है कि वर्ष 2020 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विनिर्माण केन्द्र भी बन जाएगा। जनसंख्या के सकारात्मक कारकों और उच्च गुणवत्ता वाले कार्यबल की सतत उपलब्धता की मदद से हमारा देश विश्व अर्थव्यवस्था में विशेष छाप छोड़ सकता है। भविष्य के बाजारों के लिए कौशल विकास से लेकर मानव संसाधन विकसित करने के लिए हाल में ही घोषित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से अवश्य ही हमारी अर्थव्यवस्था को पूर्ण लाभ मिलेगा। नई नीति के तहत मिशन के तौर पर लागू की गई यह योजना मानव संसाधन और उद्योग के विकास में एक नए युग की शुरुआत करेगी। वर्तमान की कौशल विकास योजनाएं प्रशिक्षण, दक्षता और रोजगार तीनों को पूरा करता है। इस तरह की योजना से देश के विकास में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी अभियान "मेक इन इंडिया" के पूरक के रूप में इसका महत्व कही अधिक है। देश में बेरोजगारी जैसी भयावह स्थिति से निपटने के लिए भी ऐसी जरुरत महसूस की जा रही है। इससे यह आशा की जा सकती है कि देश में उद्यमशीलता की उभरती प्रवृत्ति और बढ़ते आर्थिक क्रियाकलापों में इसकी भूमिका सबसे अधिक और महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में आज देश में श्रम की जरुरत से अधिक कुशल श्रम की है। और इस दिशा में कौशल विकास जैसी योजनाएं और कार्यक्रम राष्ट्रीय आर्थिक विकास के वाहक बन सकेंगे। इससे ग्रामीण युवा सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ई–मेल: gauravkumarsss1@gmail.com